ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु कार्यक्रम

4715. श्री कमला मिश्र मधुकर : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु कितने कार्यक्रम तैयार किये हैं ;

(ख) इनकी अनुमानित लागत और पूरा होने का निर्धारित समय क्या हैं;

(ग) पूर्वी चम्पारन जिले और मोतीहारी के उन भागों के नाम क्या हैं जिन्हें इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत शामिल किया गया है ;

(घ) क्या यह सच है कि इन गांवों में विकास कार्य बहुत मन्द गति से हो रहा है ; और

(ङ) सरकार ने स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कार्यवाही की है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय के अन्तर्गत ग्रामीण विकास के मुख्य कार्यक्रम समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम मरूभूमि विकास कार्यक्रम हैं। इन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है।

(ख) सभी कार्यक्रम निरन्तर स्वरूप के हैं । केन्द्रीय क्षेत्र में छठी योजना परिव्यय समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए 750 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए 980 करोड़ रुपये, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के लिए 175 करोड़ रुपये और मरूभूमि विकास कार्यक्रम के लिए 50 करोड़ रुपये है ।

(ग) से (ङ) इस तरह की सूचना इस मंत्रालय में नहीं रखी जाती है ।

Production of Soyabean

4716. SHRI SHANTUBHAI PATEL: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is the policy of the Government to encourage the production of Soyabean on a large scale;

(b) the production of Soyabean in the country during the last two years and the details of future plan;

(c) whether some experts have warned that displacing land under poor-man's food such as jawar and millets is fraught with danger; and

(d) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN): (a) Yes, Sir.

(b) The production of soyabean in the country during the last two years was as follows:—

Year	Production ('000 tonnes)
1980-81	442.2 (Provisional)
1981-82	464.0 (Provisional)

It is proposed to extend the area under soyabean to 18.50 lakh hectares by the end of Sixth Five Year Plan.

(c) Yes, Sir.

(d) The apprehension is not correct.